



डजिटल इंडिया अधिनियम, 2023

प्रलिस के लयः

डजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT अधिनियम), 2000, डजिटल व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2022, साइबर सुरक्षा, कृत्रमि बुद्धमिता (AI), डीपफेक।

मेन्स के लयः

डजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, साइबर सुरक्षा।

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जलद ही डजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 अधिनियमति करेगा जो [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम \(IT Act\), 2000](#) को प्रतस्थापति करेगा।

- भारतीय संसद नवंबर 2022 में प्रस्तावति [डजिटल व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2022](#) के साथ डजिटल इंडिया अधिनियम को लागू करने की योजना बना रही है, जहाँ दोनों कानून एक-दूसरे के साथ समन्वय में काम करेंगे।

नए अधिनियम की आवश्यकता:

- IT अधिनियम, 2000 को लागू कयि जाने के बाद से डजिटल क्षेत्र को परभाषति करने के प्रयासों में कई परशोधन और संशोधन (IT अधिनियम संशोधन, 2008 तथा IT नयिम संशोधन, 2011) हुए हैं, जसिमें डेटा प्रबंधन नीतियों पर अधिक बल देते हुए इसे वनियमति कयि गया है।
- चूँकि IT अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेन-देन की रक्षा और साइबर अपराधों को परभाषति करने के लयि डजिाइन कयि गया था, वरतमान साइबर सुरक्षा परदृश्य की बारीकियों से नपिटने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था और न ही यह डेटा गोपनीयता अधिकारों को संबोधति करता था।
- नयामक डजिटल कानूनों के पूर्ण प्रतस्थापन के बनिा, IT अधिनियम साइबर हमलों के बढ़ते परषिकार और दर को बनाए रखने में वफिल रहेगा।
- नए डजिटल इंडिया अधिनियम में अधिक नवाचार, अधिक स्टार्टअप को सक्षम करके और साथ ही सुरक्षा, वशिवास एवं जवाबदेही के मामले में भारत के नागरिकों की रक्षा करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लयि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परकिल्पना की गई है।

डजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के तहत संभावति प्रावधान क्या हैं?

- अभवियक्तकी स्वतंत्रता:**
 - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी संतुलति नीतियों को अब अभवियक्तकी स्वतंत्रता और मूल अभवियक्तकी अधिकारों के लयि संवैधानकि सुरक्षा तक सीमति कयि जा सकता है।
 - सूचना और प्रद्यूगिकी नयिम, 2021 में अक्टूबर 2022 के एक संशोधन में कहा गया है कप्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्र अभवियक्तकी अधिकारों का सम्मान करना चाहयि।
 - सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री संबंधी शकियातों के नविरण के लयि अब तीन शकियात अपीलीय समतियों की स्थापना की गई है।
 - इन्हें अब डजिटल इंडिया अधिनियम में शामिल कयि जाने की संभावना है।
- ऑनलाइन सुरक्षा:**
 - यह अधिनियम [कृत्रमि बुद्धमिता \(AI\)](#), [डीपफेक](#), साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतसिपर्द्धा के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को

शामल करेगा।

- सरकार ने 2022 में एक डजिटल परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार किया, जो डजिटल इंडिया एक्ट के चार पहलुओं में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रीय डेटा शासन नीति तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के साथ-साथ डजिटल इंडिया अधिनियम के तहत तैयार किये गए नयिम भी शामिल हैं।

■ नया न्यायिक तंत्र:

- ऑनलाइन किये गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिये एक नया "न्यायिक तंत्र" लागू होगा।

■ सेफ हार्बर:

- सरकार साइबर स्पेस के एक प्रमुख पहलू- 'सेफ हार्बर' पर पुनर्विचार कर रही है, यह एक सदिधांत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा किये गए पोस्ट के लिये उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति देता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 जैसे नयिमों द्वारा हाल के वर्षों में इस शब्द पर लगाम लगाई गई है, जिसके लिये सरकार द्वारा ऐसा करने का आदेश दिये जाने पर या कानून द्वारा आवश्यक होने पर पोस्ट को हटाने के लिये प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता होती है।

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक:

- यह वधियक भारत के भीतर डजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन डजिटल रूप में एकत्र किया जाता है। यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिये है तो यह भारत के बाहर इस तरह के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा।
- व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिये संसाधित किया जा सकता है जिसके लिये व्यक्ति ने सहमति दी है। यह सहमति कुछ मामलों में मानी जा सकती है।
- डेटा फडियूशरी (नयिमक) डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसका उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिये बाध्य होंगे।
 - "डेटा फडियूशरी" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
- यह बलि लोगों को कई अधिकार प्रदान करता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने, सुधार करने, हटाने और शिकायत नविवरण का अधिकार शामिल है।
- केंद्र सरकार वशिष्ट कारणों से जैसे- राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम करने में शासकीय एजेंसियों को बलि के प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकती है।
- बलि की आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के मामलों को तय करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी।

अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून:

■ यूरोपीय संघ मॉडल:

- सामान्य डेटा संरक्षण वनियम व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिये व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
- यूरोपीय संघ में नजिता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहित है जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करने हेतु लक्षित है।

■ संयुक्त राष्ट्र मॉडल:

- अमेरिका में गोपनीयता अधिकारों या सदिधांतों के लिये कोई समग्र वनियम नहीं है जैसा कि EU का GDPR, जो डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण को वनियमित करता है।
- इसके बजाय यह सीमिति क्षेत्र-वशिष्ट वनियमन है। सार्वजनिक और नजि क्षेत्रों के लिये डेटा सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अलग है।
 - गोपनीयता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानून के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी तथा सरकार की गतिविधियों और शक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित एवं सूचित किया गया है।
 - नजि क्षेत्र के लिये कुछ क्षेत्र आधारित वशिष्ट मानदंड हैं।

■ चीन मॉडल:

- पछिले 12 महीनों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जारी किये गए नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (PIPL) शामिल है जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
 - यह चीनी डेटा वनियमकों को नए अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
 - डेटा सुरक्षा कानून (DSL), जो सितंबर 2021 में लागू हुआ, व्यावसायिक डेटा को उनके महत्त्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। DSL सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध आरोपित करता है।

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-india-act-2023>

